



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2013/आश्विन 17, 1935

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2013/ASVINA 17, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अक्टूबर, 2013

सं. टीएमपी/26/2013—केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) में वर्थ सं. 15 के लिए दरमान की अधिसूचना हेतु मै. जेआरई इंफा प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुए प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/26/2013—केपीटी

मै. जेआरई इंफा प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

कोरम :

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम्, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितम्बर, 2013 के 25वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) में वर्थ सं. 15 के लिए दरमान की अधिसूचना हेतु मै. जेआरई इंफा प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुए प्रस्ताव से संबंधित है।
2.1. मै. जेआरई इंफा प्राइवेट लिमिटेड ने एक पत्र सं. जेआरईआईपीएल/68/2013-14 दिनांक 1 अगस्त, 2013 भेजा था जिसमें उसने जेआरईआईपीएल के पक्ष में प्रशुल्क अधिसूचना जारी करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था। जेआरईआईपीएल द्वारा अपने पत्र में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है :-

- (i) जेआरईआईपीएल केपीटी में बर्थ सं. 15, बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ (लिकिवड तथा कंटेनर से इतर), का रियातप्राप्तकर्ता है।
- (ii) बर्थ सं. 15 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जेआरईआईपीएल ने काम पूरा होने/अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केपीटी को आवेदन किया था। समानान्तरतः, जेआरईआईपीएल संबद्ध प्राधिकरियों से अन्य अनुमतियाँ/निकासियाँ अंजित करने की प्रक्रिया में हैं।
- (iii) केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2013 द्वारा जीआरईआईपीएल को प्रशुल्क अधिसूचना के लिए सीधे टीएमपी के पास जाने की सलाह दी थी। जेआरईआईपीएल ने केपीटी के पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2013 की प्रति संलग्न की है।

2.2. जेआरईआईपीएल ने अपने ऊपर उल्लिखित पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को शुरू करने से पहले इसके दरमान अधिसूचित करने का अनुरोध किया था।

3.1. चूंकि जेआरईआईपीएल ने अपना प्रस्ताव और शर्तों का विवरण नहीं भेजा था और केपीटी में बर्थ सं. 15 में अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को शुरू करने की संभावित तारीख के बारे में भी संकेत नहीं दिया था, जेआरईआईपीएल को हमारे पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2013 द्वारा अंपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था।

3.2. प्रत्युत्तर में, जेआरईआईपीएल ने अपने पत्र सं. जेआरईआईपीएल/72/2013-14 दिनांक 12 अगस्त, 2013 अपने मसादा प्रस्तावित दरमान की प्रति भेजी थी। तथापि, जेआरईआईपीएल ने बर्थ सं. 15 में अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को शुरू करने की संभावित तारीख के बारे में नहीं बताया था।

3.3. जैसाकि इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क पर आवेदन के लिए सूचकांकन कारक निर्धारित करने के लिए जेआरईआईपीएल द्वारा प्रचालनों को शुरू करने की संभावित तारीख पूर्व-अंपेक्षित है, जेआरईआईपीएल से हमारे पत्र सं. टीएमपी/26/2013-केपीटी दिनांक 23 अगस्त, 2013 द्वारा बर्थ सं. 15 में अपने प्रचालनों के शुरू होने की संभावित तारीख के बारे में तत्काल सूचित करने का अनुरोध किया गया था।

3.4. जेआरईआईपीएल ने अपने फैक्स पत्र सं. जेआरईआईपीएल/केपीटी/79/2013-14 दिनांक 28 अगस्त, 2013 द्वारा सूचित किया है कि केपीटी में बर्थ सं. 15 में इसके प्रचालनों के शुरू होने की संभावित तारीख 9 सितम्बर 2013 है।

4.1. बर्थ सं. 15 में जेआरईआईपीएल द्वारा प्रचालनों के शुरू होने की संभावित तारीख दर्शाने के लिए और इसकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए जेआरईआईपीएल के पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2013 और 12 अगस्त, 2013 की प्रति केपीटी को अनुसारक दिनांक 4 सितम्बर, 2013 द्वारा अनुसारित हमारे पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2013 द्वारा अंग्रेषित की गई थीं। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2013 द्वारा जवाब दिया था जिसे नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	जेआरईआईपीएल का प्रस्ताव	केपीटी की टिप्पणियाँ
1.	भंडारण प्रभार (आयातित और निर्यातित किए जाने वाले कार्गो के लिए)	टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और राजपत्र सं. 167 दिनांक 1 सितम्बर, 2009 द्वारा जारी किए गए शुद्धि-पत्र के अनुसार इकाई पुनः निर्धारित करें अर्थात् दर रु. में प्रति मी.ट. प्रतिदिन।
2.	प्रचालन के शुरू होने की संभावित तारीख	26-08-2013 को, परियोजना के लिए स्वतंत्र इंजीनियर रूप में आईआईटी-मद्रास परियोजना के लिए अस्थाई कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र पहले ही जारी कर चुका है, जिसमें स्वतंत्र इंजीनियर ने प्रमाणित किया है कि “यह परियोजना सुविधित तरीके से और विश्वासपूर्वक उपयोक्ताओं की वाणिज्यिक सेवा में लगाई जा सकती है, और करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना 26-08-2013 को वाणिज्यिक प्रचालन में प्रवेश के लिए अस्थाई रूप से योग्य घोषित करता है।”

4.2. तत्पश्चात्, जेआरईआईपीएल ने अपने फैक्स पत्र सं. जेआरईआईपीएल/केपीटी/81/2013-14 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा भी अनुरोध किया था कि भंडारण प्रभार शीर्ष के अधीन खंड 4क और 4ख में भंडारण प्रभार “(दर रु. में प्रति मी.ट.)” की बजाय “(दर रु. में प्रति मी.ट. प्रतिदिन) पढ़ा जाए।

5. हमारे अनुरोध पर अपने पत्र सं. टीईएसडब्ल्यू/(सामान्य)/01/पीपी दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा केपीटी द्वारा पहले प्रेषित किए गए रियायत करार के अनुसार, केपीटी ने जेआरईआईपीएल को कांडला पत्तन पत्तन में बीओटी आधार पर बर्थ सं. 15 बहुउद्देशीय कार्गो के विकास (लिकिवड/कंटेनर कार्गो से इतर) की परियोजना संभाली है। केपीटी के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर 18 फरवरी, 2011 को किए गए थे और यह करार रियायत दिए जाने की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। उक्त रियायत करार के अनुच्छेद 8.1. में विनिर्दिष्ट किया गया है कि रियायत प्राप्तकर्ता परिशिष्ट-12 में निर्धारित प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार परियोजना सुविधाओं और सेवाओं के उपयोक्ताओं से प्रशुल्क वसूल करने के लिए हककार होगा। चार बहुउद्देशीय कार्गो वर्षों के निर्माण के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए शुद्धि-पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2009 के साथ परिशिष्ट प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के करार के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरमान परिशिष्ट-12 है।

6.1. अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 के अनुसार, निजी प्रचालक महापत्तन न्यास अधिनियम (एमपीटी) अधिनियम की धारा 48 के अधीन यथा अपेक्षित और 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालनों के शुरू होने से पहले उसके प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होंगे और खंड 208 में स्पष्ट किए गए सूचकांक के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। ऐसे दरमान और शर्तों का विवरण महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

6.2. महापत्तन न्यासों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008 के खंड 208 के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित किए जाते हैं परन्तु 1 जनवरी, 2008 और प्रासारित वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही, और समायोजित प्रशुल्क प्रासारित वर्ष के 1 अप्रैल, से अनुगमी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी होगा।

6.3. अपफ्रंट प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी तदनुरूपी वार्षिक वृद्धि हमारे पत्र सं. टीएएमपी/12/2009—विविध दिनांक 2 अप्रैल 2013 द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को पहले ही संप्रेषित कर दिए गए थे।

6.4. संदर्भित सुविधा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के दरमान के खंड 6 [अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी] के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं 1 जनवरी, 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डल्यूपीआई में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति में सूचकांकित करना होगा। तदनुसार, संदर्भित मामले में लागू किया जाने वाला वृद्धि कारक दरमान के खंड 6 के साथ पठित हमारे पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2013 के अनुसार 26.15 प्रतिशत है।

7.1. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i) इस प्राविकरण ने कांडला पत्तन न्यास में बीओटी आधार पर 13वें से 16वें बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के निर्माण के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए एक आदेश सं. टीएएमपी/35/2008—केपीटी पारित किया था जिसे राजपत्र सं. 192 द्वारा 12 नवम्बर, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात, शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई, 2009 भंडारा प्रभार की बसूली इकाई को ‘प्रति मी.ट.’ से ‘प्रति मी.ट. प्रतिदिन’ में बदलते हुए राजपत्र सं. 167 द्वारा 1 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। केपीटी ने केपीटी में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं. 15 के निर्माण की परियोजना मैं जेआरई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (जेआरईआईपीएल) को सौंपी है और 30 वर्षों की अवधि के लिए 18 फरवरी, 2011 को रियायत करार किया है।
- (ii) जैसाकि पहले बताया गया है, अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.9.1 निजी प्रचालक से अपेक्षा करता है कि वाणिज्यिक प्रचालनों को शुरू किए जाने से पहले उसके प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राविकरण का रुख करे। तदनुसार, जेआरईआईपीएल ने 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के के अधीन यथा अपेक्षित दरमान अधिसूचित करने के अनुरोध के साथ इस प्राविकरण का रुख किया है।
- (iii) जेआरईआईपीएल द्वारा यथा प्रतिवेदित, प्रचालक को उम्मीद है कि वाणिज्यिक प्रचालन 9 सितम्बर, 2013 से शुरू होंगे। केपीटी ने भी सूचित किया है कि परियोजना के लिए स्वतंत्र इंजीनियर ने प्रमाणित किया है कि यह परियोजना 26-08-2013 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए अस्थाई रूप से योग्य है। जेआरईआईपीएल तथा केपीटी द्वारा प्रतिवेदित स्थिति पर विश्वास करते हुए, यह प्राविकरण ऐसी अनुमोदित दरों के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकन के संदर्भ में समायोजन के अधीन अक्टूबर 2008 में अनुमोदित दरमान की अधिसूचना के लिए जेआरईआईपीएल के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त है।
- (iv) केपीटी ने जेआरईआईपीएल के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रेषित करते समय बताया है कि अनुसूची 4 – भंडार प्रभार के अधीन जेआरईआईपीएल द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभारों के लिए वसूली की इकाई (क) आयात के लिए और (ख) निर्यात के लिए इस प्राविकरण द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई 2009 के अनुसार ‘प्रति मी.ट. प्रतिदिन’ रूप में शोधित किया जाना चाहिए। जेआरईआईपीएल भी केपीटी की इस बात से सहमत है। जेआरईआईपीएल द्वारा प्रस्तावित दरमान तदनुसार ‘प्रति मी.ट. प्रतिदिन’ रूप में भंडारण प्रभार के लिए वसूली की इकाई निर्धारित करते हुए उसी सीमा तक शोधित किया गया है।
- (v) 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार, खंड 2.9.1 के अनुसार निजी प्रचालक के लिए इस प्राविकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होना चाहिए और पहले स्पष्ट किए गए अनुसार सूचकांकन के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किया जाना चाहिए। जेआरईआईपीएल द्वारा केपीटी के साथ किए गए रियायत करार का परिशिष्ट-12 शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई 2009 के साथ चार बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के कवर के अधीन इस प्राविकरण द्वारा अधिसूचित दरमान देखा गया है।
- (vi) 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अधीन यथा अपेक्षित आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में, 26.15 प्रतिशत का वृद्धि कारक नवम्बर 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर लागू किया गया है। जेआरईआईपीएल ने उक्त प्रशुल्क आदेश में यथा निर्धारित दरों को लागू करने को शासित करने वाली शर्तों के साथ नवम्बर 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर 26.15 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू करते हुए मसौदा प्रस्तावित दरमान तैयार किया है। यह अक्टूबर 2008 के आदेश द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क मर्द में हैं जो लागू वृद्धि कारक को लागू किए जाने के मद्देनजर बदलाव किए जाने के अधीन है। अनुवर्ती वर्षों के लिए भी, जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के जनवरी के बीच आने वाले डल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकन आदेश सं. टीएएमपी/35/2008—केपीटी दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क के संदर्भ में होना चाहिए ना कि इस आदेश में अनुमोदित सूचकांकित दरमान के संदर्भ में। आदेश दिनांक 2008 में अनुमोदित सामान्य टिप्पणी को बनाए रखते हुए जेआरईआईपीएल द्वारा प्रस्तावित अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी, इससिले, इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त संशोधित की गई है। आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के दरमान में यथा अनुमोदित दरों को लागू करने को शासित करने वाली सभी अन्य शर्तों को बनाए रखा गया है। जैसाकि पहले बताया गया है, भंडारण प्रभार की वसूली की इकाई उक्त आदेश के लिए जारी शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई 2009 के अनुसार निर्धारित की गई है।
- (vii) 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार जो अक्टूबर 2008 के प्रशुल्क आदेश के पैरा 10.3 में दोहराया गया है, यदि दरमान और शर्तों के विवरण के स्पष्टीकरणों अथवा निर्वचन की अपेक्षा करते हुए कोई प्रश्न उठता है तो वह मामला इस प्राविकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में इसका निर्णय प्रचालक पर बाध्यकारी होगा।
- (viii) जेआरईआईपीएल को बोली दस्तावेजों/रियायत करार में दिए गए कार्यनिषादन मानकों से कम निष्पादन करने की उम्मीद है। जेआरईआईपीएल का वास्तविक कार्यनिषादन इस प्राविकरण द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यदि सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो यह प्राविकरण ऐसे आरोप की जांच करेगा और अपने निकर्ष कांडला पत्तन न्यास को अग्रेषित करेगा। यदि जेआरईआईपीएल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी होगी तो कांडला पत्तन न्यास रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

(ix) टर्मिनल में वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर, जेआरईआईपीएल को कांडला पत्तन न्यास के माध्यम से इस प्राधिकरण को एक रिपोर्ट जमा करने का निदेश देता है जिसमें पिछले तीन महीनों के दौरान वर्थ का भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन शामिल हो।

7.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केपीटी में जेआरईआईपीएल द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बहुउद्देशीय वर्थ सं. 15 के लिए दरमान अनुमोदित करता है जिसे अनुवृथ्य रूप में संलग्न किया गया है।

7.3. जेआरईआईपीएल के लिए अधिसूचित दरमान केपीटी में जेआरईआईपीएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत की तारीख से प्रभावी होगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 143 / 13]

अनुबंध

जेआरई इंफा प्राइवेट लिमिटेड

दरमान

परिभाषाएं

इस दरमान में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षा नहीं करता है, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

- (i) “तटीय पोत” का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii) “विदेशी पोत” अर्थात् तटीय पोत से इतर कोई पोत।
- (iii) “प्रतिदिन” अर्थात् प्रत्येक केलेंडर दिवस जबतक कि अन्य उल्लिखित न किया गया हो।

1.2. सामान्य निवंधन और शर्तें

- (i) पोत की हैसियत, कस्टम अथवा जहाजरानी महानिवेशालय द्वारा इसके प्रमाणन द्वारा यथा प्रकट, यह निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कारक है कि क्या पोत संबंधित प्रभारों की क्षुली के प्रयोजन के लिए पोत ‘तटीय’ अथवा ‘विदेशगामी’ है; और, तब कार्गो की प्रकृति अथवा इसके मूल का इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।
- (ii) (क) सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ख) ताप कोयला से इतर सभी तटीय कार्गों के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गों संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ग) कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान-टट स्थानांतरण के लिए और घाट से भंडारण यार्ड/भंडारण यार्ड से घाट तक स्थानांतरण के लिए घाटशुल्क सहित सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जाएंगी।
(घ) विदेशी पोत से कार्गो, जो भारतीय पत्तन ‘ख’ को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए पत्तन ‘क’ पहुंचता है, इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे। अन्य शब्दों में, तटीय नौचालन करने के लिए अनुमत पोत द्वारा ढोए जाने वाले भारत से/को कार्गो रियायत के लिए पात्र होंगे।

(iii) विलंबित भुगतानों/वापसियों पर व्याजः

- (क) इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर उपयोक्ता को दंडात्मक व्याज अदा करना होगा। इसी प्रकार, विलंबित वापसियों पर टर्मिनल प्रचालक को दंडात्मक व्याज अदा करना होगा।
- (ख) दंडात्मक व्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।
- (ग) वापसियों में विलंब की गिनती सेवाओं के पूरा होने की तारीख से केवल 20 दिन अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर, जो भी बाद में हो, की जाएंगी।
- (घ) उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल दिए जाने के बाद केवल 10 दिन गिनती किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाता है जहां इस दरमान में एक शर्त के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा।
- (iv) सभी परिणामित प्रभार बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।
- (v) टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य उचित स्तर से अधिक विलंबों के लिए उपयोक्ताओं को प्रभारों की अदायगी करनी होगी।

2. वर्थ किरणा प्रभारः

पोत के मास्टरों/स्वामियों/एजेंटों द्वारा देय बर्थ किराया प्रभार और बर्थ के समीप पहुंचने वाले अथवा खड़े रहने वाले फ्लोटिंग क्राफ्ट निम्नलिखित दरों के अनुसार होंगे:-

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग	
		विदेशगामी पोत (₹ में)	तटीय पोत (₹ में)
1.	सभी पोत	1.24	0.74

टिप्पणियां :

- बर्थ किराये की अवधि पोत द्वारा बर्थ अभिग्रहण किए जाने के समय से परिगणित होगी।
- बर्थ किराये में बर्थ पर प्रदत्त सेवाओं जैसे बर्थ का अभिग्रहण, कूड़ा हटाना, बर्थों की सफाई, फायर वॉच आदि के लिए प्रभार हैं।
- उस अवधि के लिए बर्थ किराया वसूल नहीं किया जाएगा जब पोत टर्मिनल प्रचालक के उपस्कर के खराब होने अथवा बिजली नहीं होने अथवा टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य किर्ती अन्य कारणों से इसके बर्थ में एक घंटे अथवा उससे अधिक समय तक लगातार निष्क्रिय रहते हैं।
- (क) पोत द्वारा नौचालन के लिए तैयार होने का सिग्नल देने के 4 घंटे बाद बर्थ किराया रुक जाएगा।
(ख) बर्थ किराये के सेवेशन के लिए निर्धारित 4 घंटों की समय सीमा में पक्षीय ज्वारभाटा स्थिति, खराब मौसम, और रात्रि नैविगेशन की कमी होने की वजह से जलयान का प्रतीक्षा समय अतिरिक्त होगा।
(ग) पोत का मास्टर/एजेंट पक्षीय ज्वारभाटा और मौसम परिस्थितियों के अनुसार ही नौचालन के लिए तैयार होने का सिग्नल देगा।
(व) झूटे सिग्नल के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभार के समकक्ष होगा।

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

कार्गो के आयातक द्वारा सीधे तोर पर विनिहित कार्गो पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर देय होंगे:-

क्र.सं.	घटक	दरें रुपयों में (प्रति टन)	
		विदेशी	तटीय
(क).	खाद्यान्न तथा उर्वरक	238.65	143.19
(ख).	ताप कोयला	178.89	178.89
(ग).	कोयला (ताप कोयला से इतर), चूनापथर, खनिज, चीनी, नमक, आदि	178.89	107.34
(घ).	अन्य शुक्र बल्क	397.32	238.40
(ङ).	स्टील और बैग कार्गो	447.25	268.36
(च).	लकड़ी के लट्टे	716.00	429.60

टिप्पणी :

ऊपर निर्धारित प्रहस्तन प्रभार (i) पोत से कार्गो की उत्तराई, स्टेकयार्ड में 5 दिनों के लिए निःशुल्क अवधि तक भंडारण के लिए इसके भंडारण प्लाइंट तक स्टीवडोरिंग तथा स्थानांतरण और आयात कार्गो के मामले में ट्रकों पर लदाई सहित (ii) 15 दिनों की अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, स्टेकयार्ड में ट्रकों से कार्गो की उत्तराई और स्टीवडोरिंग सहित जलयान पर लदाई के लिए समेकित प्रभार है। इस समेकित प्रभार में घाटशुल्क और लेबर की आपूर्ति, जहां कहीं आवश्यक हो, शामिल है।

4. भंडारण प्रभार:

स्थीकृत निःशुल्क अवधि के बाद स्टेकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होगा:-

(क) आयात के लिए

(दर रु. में प्रति मीट्र. प्रतिदिन)

क्र.सं.	घटक	छठे दिन से बीसवें दिन के लिए दर	तेरहवें दिन से उन्नीसवें दिन के लिए दर	बीसवें दिन से आगे के लिए दर
(क).	सभी प्रकार के कार्गो	12.62	18.92	25.23

(ख) निर्यात के लिए

क्र.सं.	घटक	सोलहवें दिन से बाइसवें दिन के लिए दर	तेहसवें दिन से उन्तीसवें दिन के लिए दर	तीसवें दिन से आगे के लिए दर
(क).	सभी प्रकार के कार्गो	12.62	18.92	25.23

उपर्युक्त खंडों 4 (क) और 4 (ख) के लिए टिप्पणियाः

- आयात कार्गो के लिए पांच निःशुल्क दिवस और निर्यात कार्गो के लिए पन्द्रह निःशुल्क दिवस स्थीकृत किए जाएंगे। निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, कस्टम अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के गैरकार्य दिवस अतिरिक्त होंगे।
- भंडारण प्रभार टर्मिनल के गैरकार्यदिवसों और निर्धारित निःशुल्क दिवसों के बाद कार्गो रखने के लिए कस्टम अधिसूचित अवकाशदिवसों सहित सभी दिनों के लिए देय होंगे।
- कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं जोगा जब प्रचालक उपयोक्ता द्वारा कार्गो डिलीवरी करने/नौमरण करने के लिए अनुरोध किए जाने पर टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य कारणों की वजह से ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो।

5. विविध प्रभार

क्र.सं.	घटक	दर रुपयों में (प्रति टन)
(क)	सभी प्रकार के कार्गो	19.63

ऊपर निर्धारित विविध प्रभार सभी विविध सेवाओं जैसे घाट पर कार्गो की सफाई, कार्गो का भारतोलन, धूल निवारण आदि के प्रावधान के लिए समेकित प्रभार हैं।

6. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी:

जेआरई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दरमान में निर्धारित प्रशुल्क सीमाएं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवेश सं. टीएएसपी/35/2008—केपीटी दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा अनुमोदित अपक्रंट प्रशुल्क और 1 जनवरी 2008 से प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में मिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांक लागू करते हुए सुविचारित की गई हैं। अनुवर्ती वर्षों के लिए भी, आदेश सं. टीएएसपी /35/2008—केपीटी दिनांक 14 अक्टूबर 2008 में अनुमोदित अपक्रंट प्रशुल्क सूचकांकित किया जाएगा परन्तु 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक में 60 प्रतिशत मिन्नता तक ही। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd October, 2013

No. TAMP/26/2013-KPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from M/s. JRE Infra Private Limited for notification of Scale of Rates for Berth No.15 at Kandla Port Trust (KPT) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/26/2013-KPT

M/s. JRE Infra Private Limited

...

Applicant

QUORUM:

- Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on 25th day of September 2013)

This case relates to the proposal received from M/s. JRE Infra Private Limited for notification of Scale of Rates for Berth No.15 at Kandla Port Trust (KPT).

2.1. M/s. JRE Infra Private Limited (JREIPL) has sent a letter bearing no.JREIPL/68/2013-14 dated 1 August 2013 requesting this Authority to issue tariff notification in favor of JREIPL. The main points made by JREIPL in its letter are summarized below:

- (i) JREIPL is the concessionaire of Berth no.15, a multi-purpose cargo berth (other than liquid and container) on BOT basis, at KPT.
- (ii) The construction work of Berth no.15 is complete and JREIPL have applied to KPT for issuance of completion/provisional certificate. Simultaneously, JREIPL is in the process of acquiring other permissions/clearances from the concerned authorities.
- (iii) The KPT has advised JREIPL vide letter dated 19 July 2013 to directly approach TAMP for tariff notification. JREIPL has enclosed a copy of KPT letter dated 19 July 2013.

2.2. The JREIPL vide its above referred letter has requested this Authority to notify its Scale of Rates (SoR) before commencement of its commercial operations.

3.1. Since JREIPL had not furnished its proposed SoR and statement of conditions and had also not indicated the likely date of commencement of its commercial operations at Berth No.15 at KPT, JREIPL vide our letter dated 6 August 2013, was requested to furnish the requisite information.

3.2. In response, the JREIPL vide its letter no. JREIPL/72/2013-14 dated 12 August 2013 has furnished a copy of its draft proposed SoR. JREIPL, however, did not indicate the likely date of commencement of its commercial operations at Berth No.15.

3.3. As the likely date of commencement of operations by JREIPL is prerequisite for determining the indexation factor for application on the upfront tariff notified by this Authority vide Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008, the JREIPL was again requested vide our letter No.TAMP/26/2013-KPT dated 23 August 2013 to indicate immediately the likely date of commencement of its operations at Berth No.15.

3.4. The JREIPL vide its fax letter No.JREIPL/KPT/79/2013-14 dated 28 August 2013 has informed that the likely date of commencement of its operations at Berth No.15 at KPT is 9 September 2013.

4.1. A copy each of JREIPL's letters dated 1 August 2013 and 12 August 2013 was forwarded vide our letter dated 23 August 2013 followed by reminder dated 4 September 2013 to the KPT, inviting its comments and also for indicating the likely date of commencement of operations by JREIPL at Berth No.15. The KPT vide its letter dated 07 September 2013 has responded as given below :

Sl. No.	Proposal of JREIPL	Comments of KPT
1.	Storage Charges (For cargo imported and to be exported)	Reframe the unit in accordance with TAMP Order No.TAMP/35/2008 dated 14 October 2008 and the Corrigendum issued vide Gazette No.167 dated 1 September 2009 i.e. Rate in Rs. Per MT per day.
2.	Likely date of commencement of the operation	On 26.08.13; IIT-Madras being Independent Engineer for the project has already issued the Provisional Completion Certificate for the project, wherein Independent Engineer certified that "the project can be safely and reliably placed in commercial service of the users thereof, and in terms of the Agreement, the Project is hereby provisionally declared fit for entry into commercial operation on 26.08.2013."

4.2. Subsequently, the JREIPL has also vide its fax letter No.JREIPL/KPT/81/2013-14 dated 10 September 2013 requested that the Storage Charges at Clause 4A and 4B under the head Storage Charges be read as "(Rate in Rs. Per MT per Day)" instead of "(Rate in Rs. Per MT)".

5. As per the Concession Agreement furnished by KPT earlier vide its letter no.DESW/ (GEN)/01/PPP dated 08 May 2013 at our request, the KPT has awarded the project of Development of Multipurpose Cargo (Other than Liquid/Container Cargo) Berth No.15 on BOT basis at Kandla Port to JREIPL. The Concession Agreement with KPT has been signed on 18 February 2011 and the agreement is valid for a period of 30 years from the date of award of concession. Article 8.1 of the said Concession Agreement stipulates that the concessionaire shall be entitled to recover tariff from the users of the project facilities and services as per the tariff notification set out in Appendix -12. The Appendix - 12 is the Scale of Rates notified by this Authority under cover of the tariff Order dated 14 October 2008 read with Corrigendum dated 28 July 2009 fixing upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths.

6.1. As per Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff, the private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of the Major Port Trusts (MPT) Act and as per

Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

6.2. As per clause 2.8 of guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Ports, 2008, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

6.3. The base year for the upfront tariff and the corresponding annual escalation with effect from 1 April 2013 were already communicated to all the Major Port Trusts including KPT vide our letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 2 April 2013.

6.4. As per clause 6 [General Note to Schedule (2) to (5)] of the Scale of Rates of the upfront tariff Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff for the facility in reference, tariff caps have to be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. Accordingly, the escalation factor to be applied in the case in reference is 26.15% as per our letter dated 2 April 2013 read with clause 6 of the Scale of Rates.

7.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) This Authority has passed an Order No. TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 fixing upfront tariff based on the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of upfront tariff for construction of 13th to 16th multipurpose cargo berths on BOT basis at Kandla Port Trust which was notified in the Gazette of India on 12 November 2008 vide Gazette No.192. Subsequently, a Corrigendum dated 28 July 2009 was notified in the Gazette of India on 1 September 2009 vide Gazette No.167 changing the unit of levy of storage charges from "per MT" to "per MT per day". The KPT has awarded the project of construction of multipurpose cargo berth No.15 at KPT to M/s. JRE Infra Private Limited (JREIPL) and entered into a Concession Agreement on 18 February 2011 for a period of 30 years.
- (ii) As brought out earlier, Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff requires the private operator to approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations. Accordingly, the JREIPL has approached this Authority with a request to notify the Scale of Rates as required under the Tariff Guidelines of 2008.
- (iii) As reported by the JREIPL, the operator expects that the commercial operations will commence w.e.f. 9 September 2013. The KPT has also informed that the Independent Engineer for the project has certified that the project is provisionally fit for commercial operation on 26.08.2013. Relying on the position reported by JREIPL and by the KPT, this Authority is inclined to entertain the proposal of JREIPL for notification of the Scale of Rates approved in October 2008 subject to adjustment with reference to the indexation of the rates so approved to WPI to the extent of 60%.
- (iv) The KPT, while furnishing its comments on the proposal of JREIPL, has pointed out that the unit of levy for Storage Charges proposed by JREIPL under Schedule 4 – Storage Charges, (A) For Import and (B) For Export should be corrected as "per MT per day" as per the Corrigendum issued by this Authority dated 28 July 2009. The JREIPL has also agreed with this point of KPT. The SOR proposed by JREIPL is accordingly corrected to that extent prescribing the unit of levy for storage charge as "per MT per day".
- (v) As per Clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority for the private operator as per Clause 2.9.1 should be in line with the tariff caps prescribed for the Port and included in the bid document, subject to indexation as explained earlier. The Appendix - 12 to the Concession Agreement entered by JREIPL with KPT is seen to be the Scale of Rates notified by this Authority under cover of the tariff Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths, read with Corrigendum dated 28 July 2009.
- (vi) With reference to the indexation of the upfront tariff fixed vide Order dated 14 October 2008 as required under Clause 2.8. of the 2008 Guidelines, an escalation factor of 26.15% is applied on the tariff caps notified in November 2008. The JREIPL has drawn up the draft proposed SOR applying the escalation factor of 26.15% on the tariff caps notified in November 2008, along with the conditionalities governing the application of rates as prescribed in the said tariff Order. It is only the tariff items notified vide Order of October 2008 that have been subjected to change in view of the application of applicable escalation factor. For the subsequent years as well, the indexation to the extent of 60% of the WPI occurring between January 2008 and January of the relevant year has to be with reference to the tariff approved vide Order

no.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 and not with reference to the indexed Scale of Rates approved in this Order. The General note to Schedule (2) to (5) proposed by JREIPL retaining the general note approved in the Order dated 2008 is, therefore, suitably modified clarifying this position. All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the Scale of Rates of the Order dated 14 October 2008 are retained. As stated earlier, the unit of levy of storage charge is prescribed as per the Corrigendum dated 28 July 2009 issued to the said Order.

- (vii) As per clause 3.8.5 of the 2008 guidelines which is reiterated in para 10.3 of the tariff Order of October 2008, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.
- (viii) The JREIPL is expected to perform at least at the performance norms brought out in the bid documents/concession agreement. The actual performance of the JREIPL will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority may enquire into such allegation and forward its findings to the Kandla Port Trust. If any action is to be taken against the JREIPL, the Kandla Port Trust shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the Concession Agreement.
- (ix) During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the JREIPL is directed to submit to this Authority through the Kandla Port Trust a report containing the berth's physical and financial performance during the preceding three months.

7.2. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, this Authority approves the Scale of Rates for the Multipurpose Berth No.15 to be operated by the JREIPL at KPT attached as Annex.

7.3. The Scale of Rates notified for JREIPL will come into force from the date of commencement of commercial operations by JREIPL at KPT.

[ADVT.-III/4/Exty./143/13]

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

Annex

JRE Infra Private Limited

SCALE OF RATES

1.1. DEFINITIONS

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i) **“Coastal Vessel”** means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
- (ii) **“Foreign Vessel”** means any vessel other than a coastal vessel.
- (iii) **“Per day”** means per calendar day unless otherwise stated.

1.2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- (i) The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is ‘coastal’ or ‘foreign-going’ for the purpose of levy of vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii) (a) The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.
 (b) The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
 (c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from / to quay to / from storage yard including wharfage.
 (d) Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port ‘A’ for subsequent transhipment to Indian Port ‘B’ will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (iii) Interest on delayed payments / refunds:
 (a) The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.

- (b) The rate of penal interest will be 2% above the Prime Lending Rate of the State Bank of India.
- (c) The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (iv) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (v) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the terminal operator.

2. BERTH HIRE CHARGES:

The berth hire charge payable by masters / owners / agents of the vessel and other floating craft approaching or lying alongside the berth shall be as per the rates given below:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof	
		Foreign Going Vessel (in ₹)	Coastal Vessel (in ₹)
1.	All Vessels	1.24	0.74

Notes :

- (i) The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupies the berth.
- (ii) Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch, etc.
- (iii) No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or more due to breakdown of terminal operator's equipment or power or for any other reasons attributable to the terminal operator.
- (iv)
 - (a) Berth hire shall stop 4 hours after the time of vessel signaling its readiness to sail.
 - (b) The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather, and due to lack of night navigation.
 - (c) The master /agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.
- (v) The Penal Berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charge for a false signal.

“False signal” would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes the signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions.”

3. CARGO HANDLING CHARGES:

The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:

Sl. No.	Commodity	Rates in Rupees (Per Tonne)	
		Foreign	Coastal
(a)	Foodgrains and Fertilisers	238.65	143.19
(b)	Thermal Coal	178.89	178.89
(c)	Coal (other than thermal coal), Limestone, Minerals, Sugar, Salt, etc.	178.89	107.34
(d)	Other dry bulk	397.32	238.40
(e)	Steel and Bagged cargo	447.25	268.36
(f)	Timber Logs	716.00	429.60

Note :

The handling charges prescribed above is a composite charge for (i) unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same upto the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 5 days and loading on to trucks in respect of import cargo and (ii) unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard upto a period of 15 days, transfer the cargo to the loading point and loading on to the ship including stevedoring. This composite charge includes wharfage and supply of labour, wherever necessary.

4. STORAGE CHARGES:

The storage charges for the cargo stored in the stackyard beyond the free period allowed shall be as below:

(A) For import

Sl. No.	Commodity	Rate for sixth day to twelfth day	Rate for thirteenth day to nineteenth day	Rate for twentieth day onwards
(a)	All types of cargo	12.62	18.92	25.23

(B) For export

Sl. No.	Commodity	Rate for sixteenth day to twenty- second day	Rate for twenty-third day to twenty-ninth day	Rate for thirtieth day onwards
(a)	All types of cargo	12.62	18.92	25.23

Notes for Sections 4 (A) and 4 (B) above:

- (i) Five free days for import cargo and fifteen free days for export cargo shall be allowed. For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii) Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.

5. MISCELLANEOUS CHARGES

Sl. No.	Commodity	Rate in Rupees (per tonne)
(a).	All types of cargo	19.63

The miscellaneous charges prescribed above is a composite charge for provision of all miscellaneous services such as sweeping of cargo on the wharf, weighment of cargo, dust suppression etc.

6. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE :

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of JRE Infra Private Limited takes into consideration the upfront tariff approved by the Authority vide Order No. TAMP/35/2008-KPT dated 14 October, 2008 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October, 2008 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January, 2008 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.